

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The Motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU : Sir, I introduce the Bill.

श्री सूरजभान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जो चर्चा हुई है, उस में 26 सम्मानित सदस्यों ने हिस्सा लिया है। मैं सब का तहे-दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लास तौर पर मैं चौधरी सुन्दर सिंह, श्री राकेश, श्री पासवान, श्री जगपाल सिंह, श्री गंगवार, श्री गिरधारी लाल डोगरा, श्री अराकल, श्री राठौर, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री सत्यनारायण जटिया, श्री व्यास और दूसरे व्याधियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके साथ ही मुझे लास तौर से श्री एम० सौ० डागा का शुक्रिया अदा करना है। वे एक ही व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस बिल का विरोध किया।

16.04 hrs.

[**SHRI R.S. SPARROW** in the Chair]

बाकी सब ने इस बिल की हिमायत की है। डागा साहब ने जिन कारणों से विरोध किया, उन का जिक्र मैं बाद में कहूँगा लेकिन एक बात मैं शुरू में कहना चाहता हूँ कि इस बिल में कोई नई बात नहीं है। सरकार ने बहुत पहले से कुछ आंदर जारी किये हुये हैं, आदेश दिये हुए हैं और उन्हों को मैंने इस बिल में इनकारपोरेट किया है। यह एक किताब है, जिसे मैं कभी-कभी लाल किताब कहता हूँ। यह बोशेर 370 पेज का है और इसमें सारे आदेश लिखे हुए हैं।

मैंने इस 370 पेज की किताब के बाजाए 10 सफे का एक छोटा-सा बिल आपके सामने पेश किया है। अगर यह बिल कानून की शक्ति ले ले तो हरिजनों और आदिवासियों के साथ जो साल-ब-साल ज्यादतियां हो रही हैं वे दूर हो जायें। स्वर्गीय बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने जो कुछ भी संविचान में लिखा था वह लिखा हुआ भी बगेर लिखा हुआ बन कर रह गया है। आज 37 सालों की आजादी के बाद भी मैं हरिजन और आदिवासियों के लिये यह कहने पर मजबूर हूँ—

*Published in Gazette of India Extra Ordinary Part II, Section 2 dated 27.7.1984.

हर मोड़ पर मिल जाते हैं हमदर्द हजारों
शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं ॥

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आपने
अपने शासन में उनके लिए यह बिल पास क्यों
नहीं किया ?

श्री सूरजभान : हम ढाई साल शासन में
रहे और आप 33 साल शासन में रहे हैं।
अगर हम ढाई साल में उनके लिए कुछ नहीं
कर सके तो जो हमारा हश्च हुआ आपका भी
वही हश्च होने वाला है जो कि हमारा 1980
में हुआ ।

सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस
बिल का क्या हश्च होने वाला है ? लेकिन इस
के बावजूद भी मुझे इलम है—अपनी नाका-
मियां का—मगर फिर भी बरूत आजमाने चला
हूँ। कांग्रेस पार्टी इस बिल को पास न होने
देने का इरादा कर चुकी है लेकिन फिर भी मैं
उनकी जमीर से अपील करना चाहता हूँ कि
बाबा साहेब ने संविधान में जो कुछ लिखा है
उसको तो आप अमल में लाइये। आपने इन
37 सालों में क्या किया है कि आपने एक
मटका तो उनके लिये रख दिया है इसमें ऊपर
से पानी गिरता दिखाई देता है लेकिन उसके
नीचे सुराख किया हुआ है जिससे कि पानी
की एक भी बूँद उसमें नहीं टिकती है। हरि-
जनों के साथ अब तक यही हुआ है ।

सभापति महोदय, परसों एक बात की
जानकारी मिलने के बाद मुझे बहुत हैरानी
हुई। 12 जून को नेशनल डबलपर्मेंट कौसिल
की मीटिंग हुई। उसमें सारे प्रदेशों के मुख्य
मंत्री आये। उस मीटिंग में जो कुछ डिस्कस
हुआ उस सारी बात को कांफिडेंशन रखा
हुआ है। लेकिन उस मीटिंग का जो एजेण्डा
था उसकी एक आइटम में यहां पढ़ कर सुना
रहा हूँ। उस एजेण्डे की आइटम पेरा 13 में
यह लिखा हुआ है—

“In the matter of reservations...”
Reservation means all types of reservations.

“.....particularly in educational
institutions and public services, the
question of building in an economic
criterion should be examined.”

संविधान में इकोनोमिक क्राइटरिये की
बात नहीं कही गई है। उसमें शेड्युल्ड कास्ट्स
और शेड्युल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात
कही गई है। क्या इकोनोमिक क्राइटरिये की
बात से यह साफ जाहिर नहीं होता है कि
कांग्रेस की हुक्मत यह फैसला कर चुकी
है कि सेवांश फाइव ईयर प्लान में रिजर्वेशन
को खत्म करना है ? अगर यह बात गलत
है तो यहां इसको साफ किया जाए। यह
नेशनल डबलपर्मेंट कौसिल की मीटिंग के एजेण्डे
पर है और उसकी एक आइटम रही है ।

सभापति महोदय, आप भी पंजाब के रहने
वाले हैं। आप भी इस कहावत से जौ कि
पंजाब में कही जाती है वाफिक होंगे। एक
पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरी नाक के
लिए एक नथ गड़वा दो। इस पर पति कहता
है कि तू नथ गड़वाने की बात कह रही है मैं
तेरी नाक काटने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी
ही आपकी पालिसी रिजर्वेशन के बारे में है।
हम कहते हैं कि रिजर्वेशन को इम्पलीमेंट करने
के लिये कानून बनाओ, सरकार कहती है कि
हम तो रिजर्वेशन को ही खत्म कर रहे हैं, तुम
नथ बनवाने की कह रहे हो, हम नाक काट
रहे हैं ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर
साहब इस बात का जवाब दें कि ऐसी कोई
आइटम एजेण्डे पर भी या नहीं थी। अगर भी
तो मैं जानना चाहूंगा कि उसका क्या हश्च
हुआ, क्या वह अप्रूव हो गई ? क्या आप
सातवी बोजना में रिजर्वेशन को खत्म करने
जा रहे हैं ? इसका आप जवाब दें ।

सभापति महोदय, यह तो फँकट है जो कि मैंने पढ़ कर सुनाया है इससे सरकार इंकार नहीं कर सकती है।

सभापति महोदय, इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो बात यह है कि इस बिल के जरिये से गवर्नरेट के सारे महकमों में इम्प्लीमेंटेशन में यूनीफार्मिटी लाना भेरा मक्सद है। गवर्नरेट के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग तरीके से इस पर काम हो रहा है। बैंकिंग डिवीजन को मिनिस्ट्री आफ होम बफेयर्स ने इंस्ट्रक्शन जारी की कि रिजर्वेशन से प्रमोशन होने चाहिए। 1972 में चिट्ठी जाती है और 1977 में उसको सरकुलेट करते हैं। 6 साल के बाद। 6 साल तक उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बताया गया कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने मिनिस्ट्री आफ होम बफेयर्स के आडेंस को एग्रामिन किया। कहने पर क्या एग्रामिन हो रहा है? सीबी सी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है।

तो पहला मुद्दा तो यह है कि यूनीफार्मिटी आ जाये। दूसरा मद्दा यह है कि कोडीफिकेशन, ये सब चीजें एक जगह हो जाएं जो आज नहीं हैं। तीसरा मुद्दा यह है, टू ब्रिंग क्लेरिटी एण्ड रिमूव कन्फ्यूजन, साफ शब्दों में कोई चीज लिखी जाए, कोई कन्फ्यूजन न रहे। यह कन्फ्यूजन है इसलिए सालों से कुछ नहीं हो रहा है। केन्द्र के महकमों में नहीं हो रहा। स्टेट्स में तो और बुरा हाल है।

सुंग्रीम कोट्ट का फँसला है “देयर शैल बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन” पंजाब में सर्विसेज में रिजर्वेशन है, लेकिन पंजाब में से जो हरियाणा बना है, उनमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है। तो स्टेट्स में तो और भी बुरा हाल है। गवर्नरेट आफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन हैं, कास्टी-द्यूलन में प्रावीजन है, सुंग्रीम कोट्ट का फँसला

है, लेकिन हरियाणा कहता है कि हम नहीं करेंगे।

इसको अमल में लाने के लिए मैंने इस बिल में एक पीनल ब्लाज रखी है। अभी तक इसके अभाव में अमल नहीं हो रहा है। “जो आफिसर जानबूझ कर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो पद रिजर्व किए गये हैं, चाहे रिकूटमेंट में हो, चाहे प्रमोशन में हो, अगर उन पदों को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं देते हैं तो उसको 15 दिन की कंद हो और 500 रुपए जुर्माना हो।” ये पीनल ब्लाज जब तक नहीं होगी, ये पेनल्टी जब तक नहीं होगी तब तक इम्प्ली-मेंटेशन नहीं होगा। मैं होम मिनिस्टर से कहूँगा कि मुझे 37 सालों में एक भी इस्टेंस बता दें जिसमें रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन न करने के लिए किसी भी अधिकारी को एक वानिंग तक दी गई हो। बड़ी पनिशेट को तो आप छोड़ दीजिए। इसलिए इसकी! बहरत है उन इंस्ट्रक्शंस को कानूनी भाक्ल दी जाए।

सभापति महोदय, क्या यह पालियारेट की कांपीटेंसी में भी है कि नहीं कि ऐसा कानून पास किया जा सके। कहीं ऐसा न हा कि हमारी कांपीटेंसी में न हो। धारा 246 और लिस्ट नम्बर एक, आइटम नम्बर 7, उसमें भी सेन्ट्रल गवर्नरेट सेन्ट्रल सर्विसेज के लिए कानून बना सकती है। इसी तरह से उसी धारा के तहत एंट्री नम्बर 4 लिस्ट नम्बर 20 में स्टेट के बारे में स्टेट सर्विसेज कानून बना सकती है। तीन स्टेट सर्विसेज पहले से ऐसा कानून बना चुकी हैं। उड़ीसा, बैस्ट बंगाल, मणिपुर। सेंटर को तो एक नमूना बनाता चाहिए या स्टेट्स के सामने आगर। स्टेट्स में कानून बना सकता है तो सेंटर क्यों नहीं कर सकता। मगर [बद्धकिस्मती से सेंटर इस पर कुछ कर नहीं रहा है।

सभापति महोदय, रिजर्वेशन के खिलाफ अभियान हो रहा है। नान शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आर्गेनाइजेशन्स एजीटेशन कर रहे हैं। अम्मू-कश्मीर और मध्यप्रदेश के गवर्नर, इन्हें बड़े पद पर बैठकर उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन गलत है। रिजर्वेशन का विरोध किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वे इस का विरोध कर रहे हैं। और असल में विरोध कौन कर रहा है? सीनियर क्लास बन आफिसरज।

रिजर्वेशन सभी सर्विसेज में है, लेकिन सीनियर क्लास-वन में नहीं है। क्या विद्यान में इस बात की छूट दी दुई है? डा. अम्बेडकर ने यह कहीं नहीं लिखा था:

"There shall be reservations except in senior class I services."

सीनियर क्लास-वन में रिजर्वेशन इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि एकजीक्युटिव आर्डर्स, वही लोग इश्यु करते हैं। खुद के ऊपर तो लाग नहीं किया और Non S/C S/T क्लास-श्री और कोर्ये के लोगों को कहते रहो कि हम तुम्हे सहारा देंगे। नान शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स आर्गेनाइजेशन्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है जबकि शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स आर्गेनाइजेशन्स को मान्यता नहीं दी जा रही है। अगर, आप सिन्सीयर हैं, रिजर्वेशन को इम्पलीमेंट करने के लिए तो कानून बनाइये, जिस आधार पर मैंने बिलदिया है। इसके साथ-साथ शेड्यूल कास्ट्स आर्गेनाइजेशन्स को मान्यता दीजिए ताकि वे आपकी सहायता कर सकें। यह कहा जाता है कि कास्ट के आधार पर हम मान्यता नहीं देंगे। *Scheduled Caste is not a cast, it is a combination of castes.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): It is a collection of castes.

SHRI SURAJ BHAN : Anyway, collection of castes, but it is not a caste. I agree with you.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मान्यता दयों नहीं दी जा रही है? उनके साथ दिस्क्री-मिनेशन क्यों किया जा रहा है? परिवार में जब एक आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है कि उसका खून बनना कुछ कम है इसलिए उसे दूध और कुछ फल दिए जाएं। यह भी उस बीमार को दूध और फल देने की बात है ताकि उसकी सेहत परिवार के दूसरे लोगों की तरह ठीक हो सके। अगर इस नजरिए से रिजर्वेशन को देखेंगे तो मनों में मैल नहीं होगा। हमारे मुल्क की मौजूदा शक्ति रिजर्वेशन की बजह से है। अगर पूना पैक्ट न हुआ होता तो देश की क्या शक्ति होती, इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते।

The Government should not betray the Poona Pact.

शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ बोखा मत कीजिए। महात्मा गांधी के साथ स्व. डा. अम्बेडकर ने समझौता किया था और मुल्क भर में एजीटेशन हुआ था। डा. अम्बेडकर ने तमाम हालात को देखते हुए पूना पैक्ट किया था। हम भी |यह नहीं चाहते कि कोई शेड्यूल कास्ट व्यक्ति अगर अमीर हो गया है तो उसके बच्चे की फीस आफ की जाए। लेकिन, उसे आप डी-शेड्यूल कैसे करेंगे? यह कैसे कहेंगे कि वह शेड्यूल कास्ट नहीं रहा। शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा पूरा हो जाता तो मुझे कोई एतराज नहीं था, आप रेस्ट्रीक्शन लगा देते। आंकड़े तो मैं पहले दे चुका हूं लेकिन बोडे से आंकड़े अब भी देना चाहूंगा। केबीनेट सेक्रीटरियेट में क्लास-वन सर्विसेज में शेड्यूल कास्ट्स-नील, और शेड्यूल ट्राइब्स-नील, क्लास-टू में 9.68 परसेंट जबकि 15 परसेंट होना चाहिए था।

उसके बाद होम बिनिस्ट्री की कीगर्स देखिए—जिसकी जिम्मेदारी है कि वह इसको इम्पलीमेंट करे—वहां ब्लास बन सर्विसेज में शैड्यूल कास्ट्स में 3.83 प्रतिशत तथा शैड्ट्राइव्स में 1.57 प्रतिशत है। ब्लास टू सर्विसेज में शैड्यूल कास्ट्स में 6.51 तथा शैड्यूल ट्राइव्स में 1.32 प्रतिशत है। इसके अलावा डिफेन्स सर्विसेज, डी. डी. ए. तथा डायरेक्टोरेट और एजूकेशन आदि का तो बुरा हाल है।

मैं आपको एक हैरानी से भरा तथ्य और देना चाहता हूँ। यह बात तो समझ में आ सकती है कि किसी टैक्निकल पोस्ट के लिए कोई शैड्यूल कास्ट्स या शैड्यूल ट्राइव्स का आदमी नहीं मिलता, लेकिन कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में, जहां से हमारे अराकल साहब रिप्रेजेन्ट करते हैं और वह इनकी कांसटीटूरेंसी है, वहां के आफिसर कहते हैं कि हमें शैड्यूल कास्ट्स में से स्वीपर नहीं मिल रहे हैं। लिंगनाइट कारपोरेशन के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमें स्वीपर नहीं मिल रहे हैं। स्वीपर लगाने के लिए आप क्या देखना चाहते हो, किस बालिकिकेशन की जरूरत है? क्या आप उस की अंतर्गतों को देखना चाहते हो, उस की नाक को देखना चाहते हो या उस के रंग को देखना चाहते हो। आज आप सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत कीजिए कि देश भर में एम्प्लायमेंट एक्सचेज में लाइब रजिस्टर में कितने शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइव्स के नाम दर्जे हैं जो दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, एम्प्लायमेंट एक्सचेज के चक्कर काटते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि शैड्यूल कास्ट्स और ट्राइव्स के लोग मिलते नहीं हैं। Is there any coordination between them? एक तरफ कहा जाता है कि आदमी नहीं मिलते और दूसरी तरफ पिछले चार सालों में आपने कितनी पोस्ट्स डोरिजिंग की है, उनकी संख्या 4814 है, जिनमें ब्लास-फोर भी शामिल हैं।

जिस बात यहाँ आदरणीय सेठी जी होम बिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एकजीक्यूटिव आंडंस ही काफी हैं। उनसे ठीक काम हो रहा है। यदि उनके हिसाब से ठीक काम होता तो आज इस बिल को लाने की जरूरत न पड़ती। कोई भी आदमी क्या दिल पर हाथ रख कर यह कहने के लिए तैयार है, कोई भी सेन्ट्रल बिनिस्टर या किसी विभाग का इन्वार्जं यह कहने के लिए तैयार है कि उसके विभाग में शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइव्स की जर्ती पूरी है? कोई भी बिनिस्टर या चीफ बिनिस्टर कह दे कि इनका कोटा पूरा है। मैं कहना नहीं चाहता, लोकसभा में भी यह कोटा पूरा नहीं है, जहां से सारी इंस्ट्रक्शन ईश्यू की जाती है। चूंकि बात चली है, इसलिए कहना पड़ रहा है।

श्री जगपाल सिंह (हरिदार) : लोकसभा का हाल भी बहुत बुरा है। यद्यपि संसद को कोट नहीं करना चाहिये, लेकिन संसद में क्या हाल है, वह भी रिकांड पर आना चाहिए।

श्री सूरजभान : सेठी जी ने एक दलील दी थी कि एकजीक्यूटिव आंडंस से ही, काम चल रहा है इसलिए कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके व्यापार में कुछ कोटंस के फैसले जाना चाहता हूँ, जिनमें कहा गया है कि एकजीक्यूटिव आंडंस की कोई कीमत नहीं है। इण्डियन एक्सप्रेस में 29.12.80 को जो कुछ लिपा था, उसकी ओर मैं आपका व्यापारी चौंचना चाहता हूँ, जिसकी हैंडिंग थी—

JOB RESERVATION IN AIR INDIA STRUCK DOWN

"The Bombay High Court has struck down the Directions issued by the President of India in 1975 providing for the reservation of jobs in Air India for Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

Allowing the costs of Rs. 300/- each from Air India and the Union of India on

a writ petition filed by one Mr. B.R. Ago and others, Justice A.N. Modi said :

"The directions were outside the purview of Section 34 of Air Corporations Act of 1953 and therefore *Ultra Vires*."

और सेठी साहब कर रहे हैं कि कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। एकजीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स ही काफी हैं। लेकिन हाई कोर्ट कहता है कि एकजीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स की कोई कीमत ही नहीं है।

अब मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट करना चाहता हूँ और यह उसका भी फैसला है—इकबाल सिंह एण्ड अदसं वर्सेंज स्टेट ऑफ पंजाब reported in A.I.R. 1972 S.C. 1429.

उसका सिफं एक सैन्टेन्स पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ :

"We agree with the High Court that the executive instructions issued by the State Government are void as they amount to alteration of the rules prescribed under Section 241 of the Government of India Act."

कैसे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एकजीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स ही काफी हैं जबकि हाई कोर्ट कहता है कि वह गलत हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको मानता है। कौन सी दलील है जो आप कहते हैं इस एक्ट की जरूरत नहीं है ?

MR. CHAIRMAN : Points are adequately made. You have to take into consideration the time factor. I have given you ten minutes, in fact twelve minutes. Please wind up.

श्री सूरजभान : यह करोड़ों शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स लोगों का मसला है। होम मिनिस्टर ने बीसों दलीलें दी हैं मुझे एक एक का जवाब देना है कि माननीय बैंकटसुब्बया

कह दें कि सेठी साहब ने जो दलीलें दी थीं वह गलत हैं, मैं बैठ जाऊँगा। बरना मुझे एक एक दलील का जवाब देना पड़ेगा।

MR. CHAIRMAN : I admire. You have made all the points.

SHRI SURAJ BHAN : I have yet to make the points.

SHRI P.K. KODIYAN (Adoor) : The Minister has denied many of the arguments. He has, therefore, to make his points.

MR. CHAIRMAN : All right.

श्री सूरजभान : होम मिनिस्टर ने कह दिया कि एकजीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स के साथ-साथ कमिश्नर और शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स है, पालियामेटरी कमेटी और शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स है, यह दोनों मिल कर देख सकते हैं। यह उनकी दलील है, मुझे उस को रिफ्यूट करना है। कमिश्नर की क्या हालत है ? उसके स्टैट के सारे दफ्तर तोड़ दिये गये हैं और अब तो दो ढाई साल से कोई कमिश्नर भी नहीं हैं। पालियामेटरी कमेटी की क्या हालत है ? यह कमेटी 1968 में बनी थी। 1971 में पालियामेट के चुनाव के बाद यह कमेटी तोड़ दी गई थी। बड़ा ज्ञान भवाया तब कमेटी रिवाइज की गई। लेकिन कमेटी के टम्स आफ रेफरेंस अमेंड कर दिये गये। उस पर पांच लगा दी गई है कि वह सरकारी कर्मचारियों के केस नहीं ले सकती।

इन इंस्ट्रक्शन के बावजूद कमेटी टेकअप करती रही। यह फाइल पर लिखा हुआ है। तो कमिश्नर और कमेटी की यह हालत है, फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कमिश्नर से। कमिश्नर, पालियामेटरी, कमेटी और होम मिनिस्ट्री के बींग युप ने रिकमेन्ड किया है कि एक्ट बनना चाहिए। लेकिन नहीं बना रहे हैं।

होम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा बिल कामप्रीहैसिव नहीं है। मैं पूछता हूं कि कौन सी कमी है। आर्गूमेंट के लिए मैं माने लेता हूं कि मेरा बिल कामप्रीहैसिव नहीं है। आप बायदा कीजिये कि इसी सेशन में आप कामप्रीहैसिव बिल ले आयेगे, क्योंकि इस सेशन के बाद किस की हुक्मत आती है कुछ यथा नहीं, लेकिन आपकी तो होगी नहीं। इसलिये बायदा कीजिये कि इसी सेशन में आप बिल ले आयेगे। मैं अपना बिल वापिस ले लूंगा। हर आदमी की स्वयंहित होती है कि उसका और उसकी पार्टी का नाम संसदीय इतिहास में रहे। लेकिन मैं अपना नाम वापस लेने के लिये तैयार हूं, मुझे मन्त्रजूर है मेरी पार्टी का नाम भी न आये, लेकिन आप एक कामप्रीहैसिव बिल ले आइये, मैं अपना बिल वापस लेने के लिए तैयार हूं। कारण यह है कि मैं तो शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स का भला चाहता हूं।

गृह मंत्री जी ने बिल का जवाब देते हुए कहा कि सूरजभान जी के बिल में कमियां हैं और उसका हवाला उन्होंने यह दिया कि मैंने बलाज 20 में कहा है कि अगर कोई आदमी ठीक ढंग से पालन नहीं करता है तो 15 दिन की सजा हो। तो कुछ केसेज में तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कुछ में कोई और करता है, तो क्या उनको भी आप पनिशेंट देना चाहते हैं। मैंने इस बलाज के साथ प्रोवी जो भी रखा था जो मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

Clause 20 says :

"If an appointing authority makes an appointment in contravention of the provisions of this Act, he shall be punishable with fine which may extend to Rs. 500 or simple imprisonment for 15 days or both."

Provided that special provisions shall be prescribed by appropriate authority when the appointing authority is

other than government, public corporation, autonomous body etc."

बगर अफसरों के अलावा कोई और, एपाइन्टिंग अधीरिटी या प्रैंजीडेंट एपाइन्टमेंट देखे हैं तो एकचूबल जो एपाइन्टमेंट के आडंडर इश्यू करता है, उसको पनिश किया जाये। यह प्रावीजन उन्होंने पढ़ा नहीं।

उन्होंने कहा कि हमने इम्स्ट्रक्शन्ज इश्यू किये हैं कि सख्ती से डील किया जाये अगर कोई इम्लीमेंटेशन नहीं करता है तो। मैं पहले कह चुका हूं कि एक केस भी बता दीजिए, अगर किसी को वानिंग भी दी हो? आज तक दुआ नहीं है।

सभापति महोदय, मैं बिस्कुल आखिर में एक कम्परिजन आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा मुकाबला कर सौजिये।

यह शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्ज की हालत है एक तरफ पूरा परिवार झोपड़ी या कच्चे कोठे में बैठा है। बकरी अगर है तो वह बीच में बंधी है। बच्चों की बीख चिल्लाहट, बीमार की कराहट, भूखे पेट, बगैर लिहाफ और रजाई, कड़कती सर्दी में मिट्टी के तेल के दिये की रोशनी में पढ़ने वाला हरिजन आदिवासी है।

दूसरी तरफ ऊंचे समाज का लड़का, सुन्दर और एयरकंडीशन कमरे में बैठकर रात को दिन बना देने वाली बिजली का चकाचौथ रोशनी में पूरी सुविधाओं के साथ बलग कमरे में पढ़ता है।

हरिजन आदिवासी बगैर टाट और कुर्सी, वाले, बगैर लत वाले स्कूल में पढ़ता है और स्कूल से पहले और बाद घर के कामकाज में मां-बाप का हाथ बटाता है या मेहनत मजदूरी करता है और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा पनिक स्कूल में पढ़ता है, जहरत

पढ़ने पर टीचर घर पर आकर उसको ट्यूशन पढ़ाता है।

यानी अशं और फर्श, या दूसरे शब्दों में आकाश और वर्ती पर रहने वाले एक ही इम्तहान में बैठें, मैं ऐसे हालात में सब को समान अवसर देने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या यही तुम्हारा समाजवाद है?

इन कड़वी सचाइयों को ध्यान में रखते हुए यह रिंबेशन संविधान में की गई कि उनकी यह हालत है और दूसरों की कुछ और हालत हैं। आप सब हाउस के अन्दर और बाहर हरिजन आदिवासियों के हित की बात करते हैं, ऊँची-ऊँची आवाज में कहते हैं, आज हमारा सब का इम्तहान है। यह छोटा सा बिल है, आप उसको कानून की शक्ति देकर हरिजन आदिवासियों के साथ अपने सच्चे हमदर्द होने का सबूत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस बिल की हिमायत करेंगे और कानून की शक्ति इसे देंगे।

मैं अमेंडमेंट्स पर भी कुछ कहना चाहता हूँ। डागा साहब की अमेंडमेंट है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सकुलेट किया जाये। वह यहां हैं ही नहीं, तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह जो इन बिल को सकुलेट करना चाहते हैं, मैं उसको एक्सीट नहीं करता हूँ।

रुच और साथियों ने कहा कि सजा 15 दिन की कम रखी है, इसको 3 महीने या एक साल करो। मेरा कहना है कि यह 15 दिन ही काफी हैं, क्योंकि गवर्नरमेंट एम्प्लाई को अगर एक दिन की भी सजा हो जाय तो वह नौकरी से जाता रहेगा। इसलिये कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को नुकसान पहुँचाकर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा।

मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस बिल की हिमायत कीजिए, इसके हुक में वोट दोजिये और इसको कानून की शक्ति दीजिये।

चन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Now, I will put Amendment No. 3 moved by Shri Mool Chand Daga to the vote of the House.

Amendment No. 3 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to provide for adequate representation of Scheduled Casts and Scheduled Tribes in posts and Services under the Government of India, be taken into Consideration"

The Lok Sabha divided.

Division No. I

16:43 hrs.

AYES

Agrawal, Shri Satish

Barman, Shri Palas

Chakraborty, Shri Satyasadhan

Dhandapani, Shri C.T.

Hasda, Shri Matilal

Jagpal Singh, Shri

Khan, Shri Ghayoor Ali

Kodiyan, Shri P.K.

Mandal, Shri Sanat Kumar

Mehta, Prof. Ajit Kumar

Mirdha, Shri Nathu Ram

Mukherjee, Shri Samar

Nayar Shri A. Neelalohithadasan

Pathak, Shri Ananda

Patil, Shri J. S.

Rajesh Kumar Singh, Shri

Rasheed Masood, Shri

Roypradhan, Shri Amar	Jha, Shri Kamal Nath
Sinha, Shri Nirmal	Kamala Kumari, Kumari
Soz, Prof. Saifuddin	Kidwai, Shrimati Mohsina
Suraj Bhan, Shri	Kosalram, Shri K.T.
Vajpayee, Shri Atal Bihari	Krishna, Shri S.M.
Verma, Shri R.L.P.	Krishna Pratap Singh, Shri
Yadav, Shri R.P;	Krishnan, Shri G.Y.
NOES	
Ahmed, Shri Kamaluddin	Mishra, Shri Ram Nagina
Ajit Pratap Singh, Shri	Mishra, Shri Nityananda
Ankineedu, Shri M.	Pandey, Shri Krishna Chandra
Ansari, Shri Z. R.	Panika, Shri Ram Pyare
Anwar Ahmad, Shri	Phulwariya, Shri Virda Ram
Bairwa, Shri Banwari Lal	Poojari, Shri Janardhana
Bhagat, Shri H. K. L.	Ranga, Prof. N. G.
Bhagwan Dev, Acharya	Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Bhoi, Dr. Krupasindu	Rathod, Shri Uttam
Bhole, Shri R. R.	Reddy, Shri G. Narsimha
Brar, Shrimati Gurbrinder Kaur	Reddy, Shri K. Brahmananda
Buta Singh, Shri	Keddy, Shri M. Ram Gopal
Chennupati, Shrimati Vidya	Roat, Shri Jai Narian
Dalbir Singh, Shri	Sathe, Shri Vasant
Dass, Shri A. C.	Satya Deo Singh, Prof.
Dennis, Shri N.	Sebastian, Shri S. A. Dorai
Dev, Shri Santosh Mohan	Sethi, Shri Arjun
Dogra, Shri G. L.	Shankaranand, Shri B.
Gogoi, Shri Tarun	Sharma, Shri Kali Charan
Gomango, Shri Giridhar	Sharma, Shri Nawal Kishore
Jaffer Sharief, Shri C. K.	Shastri, Shri Hari Krishna
Jain, Shri Virdhi Chander	Singaravelivel, Shri S.
Jena, Shri Chintamani	Singh, Shri C. P. N.

Singh, Kumari Pushpa Devi

16.44 hrs.

Singh Deo, Shri K. P.

ANTI-POPULATION EXPLOSION BILL

Sinha, Shrimati Ramdulari

Shri P. RAJAGOPAL NAIDU: I beg to move :

Soren, Shri Harihar

"That the Bill to provide for measures to restrict the growth of population in the country, be taken into consideration."

Subburaman, Shri A. G.

Sunder Singh, Shri

Swami, Shri K. A.

No amendment has been moved to this Bill and, therefore, I think that the whole House is in agreement with this Bill and I am hopeful of its being passed unanimously.

Tewary, Prof. K. K.

Thomas, Shri Skariah

Tudu, Shri Manmohan

The other day Shrimati Mohsina Kidwai, in reply to a question has said that there is an increase of 25% of the population every decade in our country. The reasons she quoted are that the death-rate has lessened and birth-rate has gone up with the result that there is increase in population. She also said that people of this country have no concern at all for the growth of population. But, I differ from that. But I differ from that. When we got freedom, the population was only about 30 crores. According to the 1981 census, it was about 68 crores. Now it is crossing 70 crores. It is estimated that, by 2,000, it would be about one billion. It is because of this population growth, the misery is increasing in our country. It is not that our Government has not done anything for the improvement of the people. You can take some of these facts into consideration. For example, in 1950-51 the total irrigated area was 2,08,53,000 hectares whereas in 1976-77 it was 3,47,99,000 hectares. It has increased two fold. In the yield also there has been increase: with regard to rice, in 1950-51 it was 6.7 quintals and in 1978-79 it increased to 13.4 quintals; in regard to wheat, it was 6.6 quintals in 1950-51 and it increased to 15.7 quintals in 1978-79; in jowar it increased from 3.5 quintals to 7.2 quintals in 1978-79; in maize it increased from 5.3 quintals to 10.8 quintals. That means, even the yield has increased to a great extent. The area under principal crops also has increased. In 1970-71 it was 1,01,78,200 hectares and in 1980-81 it was 1,49,48,000 hectares. With all this increase, we are not able to feed our population to our satisfaction. Even now 50 per cent of the population are under the poverty line; they

MR. CHAIRMAN : Subject to correction the result* of the Division is as follows :

Ayes 24

Noes 68

The motion was negatived.

*The following Members also recorded their votes :

AYES : Sarvashree Gangwar, Shri Harish Kumar, Rajda, Shri Ratan Singh Kabuli, Shri Abdul Rasheed and Paswan, Shri Ram Vilas.

NOES : Sarvashree Ranjit Singh, Soheng Tayeng and Bishnu Prasad